RE. NEED TO ANNOUNCE SUPPORT PRICE FOR JUTE

श्री नरेश यादव (बिहार): महोदय, मैं आज आपके माध्यम से देश के लाखों जूट उत्पादक किसानों की समस्याओं की ओर सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज हमारा यह सौभाग्य है कि माननीय कृषि मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और मैं चाहूंगा कि उन किसानों की समस्याओं के बारे में जो जूट पैदा करते हैं, जिनको कर्ज के बदले में अपनी किडनी तक गंवानी पड़ रही है वैसे किसानों की समस्याओं पर अवश्य ध्यान देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के दादरपुर गांव के खेतिहर मजदूर सलीम मोहम्मद ने महाजन सेफा मुहम्मद की कर्ज अदायगी आठ हजार के बदले पन्द्रह हजार की, उसके बाद भी उसका कर्ज उस पर रह गया और उस किसान को झांसा देकर वह मुम्बई ले गया तथा उसकी किडनी तक ले ली। यह जूट उत्पादक किसानों की कहानी है। कृषि मंत्री जी यह पश्चिमी बंगाल और बिहार की नगदी फसल कही जाती है।

महोदया, जूट उत्पादक किसान जो पश्चिमी बंगाल और उत्तरी बिहार में लाखों की संख्या में हैं यह उनकी नगदी फसल है जिसकी लागत एक हजार से ग्यारह सौ रुपये प्रति एकड़ आती है और आज किसानों को जूट की मूल्य पांच सौ रुपये से छह सौ रुपये प्रति क्विंटल ही प्राप्त हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने 7 अगस्त, 1996 को बिहार के सबसे पूर्वी हिस्से किशनगंज में जो कि जूट उत्पादक जिलों में से एक प्रमुख जिला माना जाता है, वहां पर गए और उन्होंने वहां सभा में घोषणा की थी कि जूट के मूल्य का पुनर्निधारण किया जाएगा। उस समय जूट का मूल्य आठ सौ रुपये प्रति क्विंटल चल रहा था और जूट का मूल्य खिसक कर पांच सौ, छह सौ रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। साथ ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जूट उत्पादक वस्तुओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिन प्लास्टिक बोरों को आज पूरे देश में चलाया जा रहा है उसके बदले में जूट का बोरा देश में चलाया जाए जिससे कि जूट उत्पादक किसानों को पैसा मिल सके।

अत: मैं आज आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री का और सदन में मौजूद कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अब कोई जूट उत्पादक किसान अपनी किडनी कर्ज के बदले नहीं दे, इसके लिए आवश्यक है कि जैसे आप गन्ना किसानों के लिए मूल्य का निर्धारण कर रहे हैं उसी प्रकार से बिहार और पश्चिमी बंगाल के जूट उत्पादक किसानों के लिए पन्द्रह सौ रुपये प्रति क्विंटल जूट का मूल्य निर्धारित किया जाये, जिससे कि किसान प्राण पा सकें। पश्चिमी बंगाल के माननीय मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु ने भी जूट का मूल्य ग्यारह सौ रुपये प्रति क्विंटल करने के लिए भारत सरकार को सुझाव दिया है। महोदया, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, my point is...

THE DEPUTY CHAIRMAN: If we are going to have association of everybody...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: This is different, Madam.

THE DEPUTY CHAIRMAN: One second. I have eleven Zero Hour Mentions and eleven Special Mentions.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, I will take two minutes.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me tell the Members whose name is going to come today. This is the last day of the week. How are we going to finish it?

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Madam, we are waiting since yesterday, (*Interruptions*)

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): महोदया, मैं ...(व्यवधान)...

उपसभापति: आप बोल दीजिए, सब लोग उसमें एसोशिएट हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

कृषि मंत्री (श्री चतुरानन मिश्र): महोदया, जूट उत्पादकों की समस्या के संबंध में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है उसके संबंध में, इसके पूर्व ही मैंने माननीय सदस्या गीता मुखर्जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। वह कमेटी जांच कर रही है, जांच करने के बाद ज्यों ही रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर हम तुरन्त कार्रवाई करेंगे। जहां तक सरकार के द्वारा जूट खरीददारी का प्रश्न है तो वह टेक्सटाइल विभाग के अण्डर में आता है, वह हमारे अण्डर में नहीं है। जूट की अच्छी क्वालिटी का उत्पादन हो, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हम कमेटी की रिपोर्ट का इन्तजार कर रहे हैं। हम इसके पहले भी जूट उत्पादकों का एक सम्मेलन करके उनसे स्वयं बातचीत करना चाहते हैं। मैंने जूट इंस्टीट्यूट जो रिसर्च का है उससे कहा है कि इसके पेपर तैयार करे। ...(व्यवधान)...

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The Jute Corporation of India is not procuring. The hon. Minister should know. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: They have formed a committee. ...*(Interruptions)*... Don't interrupt him like this. You are infringing upon the right of other Members who have been sitting in the House to make their submissions. They have taken prior permission. They have a right to speak.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Madam, as I have already stated the Jute Corporation of India ...*(Interruptions)*...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया (बिहार) : यहां कोई मंत्री स्पैशल मेन्शंस या जीरा हावर सब्मिशन का रेसपॉन्स नहीं देता है लेकिन कृषि मंत्री जी यहां रेसपॉन्स दे रहे हैं। यह गलत बात है। ...(व्यवधान)

This is not fair. This is not fair. I had raised an important question. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Nilotpal Basu, please sit down. Mr. Ahluwalia, please sit down. I would like to pose a question to all the Members : What is the responsibility of the Presiding Officer? It is entirely my discretion when I ask a Minister to respond and if he has refused him, he could have got up. I felt that this is a sensitive matter. If people are dying in the country because they are not getting money for their produce, do you think that I should not ask the Minister to say something? At least my conscience doesn't permit me to keep quiet. But the issue which they raised was about a State where something was not being done. I can't ask the Minister to get up and reply. We have to go issue by issue. I think it is not proper for the Members to guide the Chair all the time. It really pains me. Why should you talk to him directly? If you have any objection you can say that Mr. Ahluwalia was using these words. You can tell me. But I have noticed that everyone gets up and speaks simultaneously. It is not loss of my time. It is loss of your time for which I am sitting here and burning my energy. I want that everything should be run in an order so that I can finish Zero Hour submissions as well as Special Mentions.

RE: BASIC TELECOM SERVICES AWARDED TO A COMPANY IN RAJASTHAN

श्री राघव जी (मध्य प्रदेश) : उपसभापति जी, पिछले दिनों यह सदन संचार मंत्रालय के घोटालों के कारण कई दिनों तक स्थगित रहा। नये संचार मंत्री आये तो उन्होंने यह वायदा किया था कि वे पिछले सारे घोटालों की जांच करेंगे और उनको ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। ...(व्यवधान)

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: कहां करने वाले हैं? ...(व्यवधान)

श्री राघव जी: मुझे लगता है कि उन्होंने इस दिशा में सुधार का कार्य करने के बजाय स्वयं उस दिशा में चल पड़े हैं। अभी राजस्थान में एक बेसिक टेलीकॉम एवार्ड जो दिया गया है वहां की एव्युलेशन कमेटी ने 1700 करोड़ रुपये का प्रोफिट तय किया जबकि टैंडर 1100 करोड़ रुपये के थे। इससे साफ जाहिर है कि 600 करोड़ रुपये का सरकार को घाटा होने जा रहा है। इस संबंध में विधि-विभाग की राय इसके खिलाफ मौजूद है। बाकी विशेषज्ञों की राय भी इसके खिलाफ मौजूद है इसके बावजूद भी नियमों की ताक पर रखकर एवार्ड पारित किया गया जिससे सरकार का 600 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। हिन्दुस्तान के प्रमुख समाचारपत्र जनसत्ता के प्रथम पृष्ठ पर जो प्रकाशित हुआ है आज तक संचार मंत्रालय द्वारा इसका कोई खंडन भी नहीं किया गया है। बाकी के जो प्रतिस्पर्धी थे उनको इस बात का मौका दिये बगैर इस कम्पनी को जो 1700 करोड़ रुपये का एवार्ड दिया गया है इसमें कोटेशन से भी ज्यादा पैसा दिया जा रहा है। यह गम्भीर मामला है इसलिए मैं सरकार का ध्यान और मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस मामले में वे अपनी सफाई दें।

RE. RESIGNATION OF CHAIRMAN OF AIR INDIA

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : महोदय, मैं आपका और सदन का ध्यान इंडियन एयरलाईंस और इअर इंडिया के फंक्शनिंग की ओर दिलाना चाहता हूं। महोदया, पिछले कुछ वर्षों से बहुत बड़ा घाटा हो रहा है। जो चीजें फायदे में जा रही थीं, एक्सपैंशन के बाद फायदा नहीं बढ़ रहा है बल्कि नुकसान हो रहा है। वायुदूत की सर्विस शुरू की,